हंगामे के बीच नगर निगम का बजट पारित

▶ सदन में विकास नहीं, हंगामा बना कार्रवाई

सभापति

नव भारत न्यूज

इंदौर. नगर निगम का सालाना बजट पक्ष विपक्ष के हंगामे के बीच पारित हो गया. हंगामे कर दौरान बजट पारित करने का प्रस्ताव एमआईसी सदस्य ने रखा और चलते हंगामे में ही सभापति ने बजट पारित करने की घोषणा कर दी. आज के बहस में भागीरथपुरा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का मुद्दा छाया रहा, लेकिन शहर के विकास और समस्याओं पर कोई सार्थक बहस नहीं हुई.

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कल नगर निगम के 8455 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसे आज सदन में बहुमत से पारित कर दिया गया. सभापति मुन्नालाल यादव ने एमआईसी सदस्य निरंजन सिंह चौहान के प्रस्ताव पर बजट पारित करने की घोषणा की. इसके साथ ही नगर निगम का 2026-27 का सालाना बजट पारित हो गया. बजट में आज भाजपा पार्षदों ने ही अपनी परिषद पर काम नहीं होने और रोकने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए. आज बजट बहस के दौरान विपक्ष ने भागीरथपुरा दूषित पानी के घटना को लेकर हंगामा किया. आज बहस की खास बात यह रही कि सभापति की आसंदी का भाजपा पार्षदों ने ज्यादा घेराव किया. शुरुआत कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के किसी मामले पर भाजपाइयों को गद्दार बोलने को लेकर हुई. भाजपा ने आपत्ति लेते हुए सभापति की आसंदी पर प्रदर्शन और नारेबाजी कर सदन से उक्त शब्द विलोपित करने की मांग की और सभापति यादव ने सदन की कार्रवाई से विलोपित करने की घोषणा की.

भागीरथपुरा घटना को लेकर की नारेबाजी-प्रश्नकाल में भाजपा पार्षदों ने कल बजट पेश करने के दौरान भागीरथपुरा पीड़ितों को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताने पर हंगामा शुरू हो गया. फिर भागीरथपुरा के पीड़ितों को आउटसोर्स नौकरी की बजाय स्थाई नौकरी देने की मांग की गई. सदन में कांग्रेस ने भागीरथपुरा की घटना को लेकर जमकर नारेबाजी और विरोध किया. इस दौरान भाजपा पार्षदों ने वंदे मातरम के नारे लगाए.

आदर्श मौलिक नगर का मुद्दा उठाया-कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया ने पूछा कितनी कॉलोनी को नियमित किया है? साथ ही पूछा कि घोषणा होती है, लेकिन अवैध कॉलोनी आज तक प्रॉपर वैध नहीं हुई. भदौरिया ने आदर्श मौलिक नगर का मुद्दा उठाया और लीज डीड होने के बाद नक्शे पास नहीं हो रहे हैं? उन्होंने कहा 110 कॉलोनी वैध करने का दावा किया गया है वो कहां और कब हुई? कॉलोनी सेल प्रभारी राजेश उदावत ने बताया कि 153 कॉलोनियों में नागरिक सुविधा प्रदान कर दी गई है. 40 कॉलोनियों में नागरिक सुविधा देने का काम चल रहा है.

हुकुमचंद मिल के पेड़ काटे जाने का विरोध किया-पार्षद जीतू जाटव ने हुकुमचंद मिल गुमटी और परिसर में पेड़ों को कटाई का सवाल किया. जाटव ने गुमटी वालों को हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था देने की अपील महापौर और आयुक्त से की. साथ ही यह मांग भी रखी की संभव हो तो यथास्थान पर ही रहने दें. पार्षद जाटव ने हुकुमचंद मिल के पेड़ काटे जाने का विरोध किया और महापौर और आयुक्त से अपील की कि पेड़ कटने से रोके जाएं. पार्षद जाटव ने आगजनी की घटना को लेकर सदन में सवाल उठाया कि आग पर काबू पाने की व्यवस्था नहीं है. शहर में छह नए फायर स्टेशन जल्दी बनाने की मांग की.

सभापति की आसंदी घेरी-नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के खड़ा होते ही भाजपा पार्षद कल दर्शक दीर्घा में भागीरथपुरा के मुद्दा उठाने के लिए माफी मांगने पर अड़े. सभी एमआईसी सदस्य सभापति के पास आसंदी पर पहुंचे और खेद जताने की मांग की. चौकसे ने कहा कि एक हजार नहीं एक लाख बार भागीरथपुरा पीड़ितों के साथ खड़े है. कांग्रेस पार्षदों ने महापौर माफी मांगो माफी मांगो के नारे लगाए.

पानी की लाइन का काम क्यों रोका?-भाजपा पार्षद लाल बहादुर वर्मा ने आक्रमक अंदाज में सवाल पूछते हुए अपनी परिषद की घेरा और कहा कि पानी की लाइन का काम क्यों रोका गया? पार्षद को प्रश्न लगाने पड़ रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारी काम रोक कर बैठे हैं. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर हटाना पड़ेगा. पार्षद वर्मा के प्रश्न से सदन में सन्नाटा छा गया. वर्मा ने फिर कहा कि पार्षद निधि रोकने का अधिकार किसी को नहीं है. क्यों रोकी है बताए? महापौर ने निविदा समिति द्वारा जारी होने के बाद भी काम नहीं होने की जांच के आदेश देने का सभापति के सामने प्रस्ताव किया. उपरोक्त मामले में सभापति ने जांच के आदेश दिए.

चंदन नगर सड़क और फ्लॉयओवर पर उठाया सवाल

पार्षद महेश चौधरी ने चंदन नगर, नंदन नगर एयरपोर्ट सड़क और चंदन नगर फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण का सवाल उठाया. जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि उक्त सड़क का निर्माण अगल महीने शुरू हो जाएगा. करीब सवा दो किलोमीटर लंबी और 60 फीट चौड़ी सड़क का ठेका दिल्ली के कंपनी को 26.83 करोड़ में दे दिया है. वहां के विस्थापितों को पीएम आवास में शिफ्टि किए जाएगा. चंदन नगर फ्लाई ओवर पहले निगम बना रहा था लेकिन अब आईडीए द्वारा उक्त ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसके टेंडर 2 माह में होकर काम शुरू हो जाएगा. एक साल में बन भी जाएगा.

गंदे पानी का मुद्दा उठाया-फौजिया शेख ने गंदे पानी का मामला उठाते हुए कहा कि पूरे शहर को मारना चाहते हो क्या? पूरे शहर और आजाद नगर और अन्य क्षेत्र में ड्रेनेज और गंदे पानी की समस्या है. इसके बाद फौजिया के सामने वंदे मातरम और भारत माता के जय मारे लगे. भाजपा पार्षदों ने कहा भारत में रहना तो जय बोलना होगी. भाजपा पार्षद सभापति की आसंदी पर पहुंचे, विरोध दर्ज करवाया और निष्कासित करने की कार्रवाई होने पर शांत हुए.

शहर और जनहित के मुद्दों पर बहस नहीं

नगर निगम के बजट बहस में आज राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और भागीरथपुरा के मुद्दे पर जेजे सदन की कार्रवाई खत्म हो गई. सभापति ने भी बजट पारित करने की घोषणा कर दी. आज बजट में शहर के मुख्य मुद्दे सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज, यातायात, अधूरे निर्माण, गंदा पानी, बगीचे, पर्यावरण, बदहाल सड़के, लेफ्ट टर्न, शमशान विकसित करने जैसे मुद्दों पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई. यह दर्शाता है कि जनहित नहीं, बल्कि हंगामा और एक-दूसरे से माफी मंगवाने तक ही निगम पार्षदों का काम रह गया है. आज बजट पर बहस ही नहीं हुई और बजट पारित हो गया. यह इस बात का प्रमाण है कि पार्षद क्षेत्र की जनता के प्रति कितने संवेदनशील है और विकास और समस्या से उनका लेना देना नहीं है. उनका मकसद सिर्फ हंगामा करना है, जो शहर वासियों के लिए अनुचित व्यवहार माना जा सकता है. शहर की चिंता किसी को नहीं है, सब मुद्दों को छोड़कर दूसरे मामलों में समय जाया करते रहे. पार्षदों के आज के व्यवहार को शहर की जनता उचित नहीं मान सकती है.

चौकसे ने नहीं मांगी माफी

भोजनकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे बजट बहस में अपनी बात रखने खड़े हुए, वैसे ही कल की घटना को लेकर एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर ने सभापति को पत्र लिखकर मांग की कि कल सदन में घटित घटना के लिए माफी मांगे. सभापति ने भी चौकसे से खेद व्यक्त करने का कहा, लेकिन चौकसे ने माफी नहीं मांग कर उल्टा माइक पर कहा कि कांग्रेस एक हजार नहीं को लाख बार भागीरथपुरा के पीड़ितों एक साथ खड़ी हेयर उनको न्याय दिलाकर ही मानेगी. इसके बाद दोनों पक्षों के हंगामे में बजट पारित करने की घोषणा हो गई.

ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे: रुबीना

आज नगर निगम बजट बैठक बहस के बाद पार्षद रुबीना खान ने चिंटू चौकसे द्वारा जीतू पटवारी को शिकायत करने की बात पर कहा कि भाड़ में जाए कांग्रेस. हमारा कोई अनुबंध थोड़ी है कि कांग्रेस में ही रहे. हम ओवैसी के पार्टी में चले जाएंगे। मुंबई में वहां कितनी सीटें जीती है. हम वहां ज्वाइन कर लेंगे.

इन्होंने भी रखी अपनी बात...

- पार्षद सीमा सोलंकी ने हंगामे के बीच भाजपा पार्षदों से कहा कि आपको हमारे परिवार को गंदा बोलने का हक नहीं है. भागीरथपुरा में आपने 36 लोगों की हत्या की है. अमित पटेल हमारी पार्षद का पति है, जिसको आप गुंडा बता रहे हो.
- एमआईसी राजेश उदावत ने नगर निगम को बहस में निगम सीमा से बाहर भोपाल यूनियन कार्बाइड की घटना जिक्र किया.
- बजट में नगर निगम के मुद्दों को छोड़ कर राष्ट्रगान, राष्ट्र गीत मुद्दा बन गया.
- अंत में कांग्रेस पार्षदों ने संविधान की हत्या करने का आरोप लगाते हुए नारे बाजी की. सभी विषय को बहुमत पर पास करने की सभापति ने घोषणा की.

एक नजर में

सैमसंग ने लॉन्च किया बीस्पोक एआई विंडफ्री प्रो एसी

इंदौर. सैमसंग ने आज होम कूलिंग में अपने नए प्रोडक्ट-5 मोशन विंड के साथ बीस्पोक एआई विंडफ्री प्रो एयर कंडीशनर लॉन्च किया है. यह प्रीमियम एयर कंडीशनर आधुनिक लग्ज़री डिजाइन के साथ आता है, जो आज के जमाने के लिविंग स्पेस के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है. इसका सुंदर और मिनिमलिस्ट डिजाइन किसी भी आधुनिक इंटीरियर में आसानी से घुल-मिल जाता है और स्थान की खूबसूरती बढ़ाता है. सैमसंग इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट - डिजिटल अप्लायंसेज, घुफ़रान आलम ने कहा सैमसंग भारत में अपनी 30वीं सालगिरह मना रहा है, और कंपनी ने नए-नए प्रोडक्ट विकसित करना और ग्राहकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक बेहतरीन समाधान देना जारी रखा है. यहां पड़ने वाली चिलचिलाती गर्मी में उपभोक्ता सिर्फ कूलिंग नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट, पर्सनलाइज्ड और एनर्जी-एफिशिएंट समाधान चाहते हैं. हमारा नया बीस्पोक एआई विंडफ्री प्रो एयर कंडीशनर प्रिसीजन एयरफ्लो और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को जोड़कर तेज कूलिंग, ड्राफ्ट-फ्री कम्फर्ट और बिजली की बेहतर बचत देता है. सैमसंग की एडवांस्ड मोशन विंड तकनीक कमरे में हवा की दिशा और स्पीड को अपने आप एडजस्ट करती है, जिससे ठंडक हर कोने में संतुलित और आरामदायक बनी रहती है.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने 18 करोड़ सिलेंडर डिलीवर किए

इंदौर. दुनिया भर में ऊर्जा के संकट के बीच ईंधन की उपलब्धता बाधित हुई है, और कई क्षेत्रों में ईंधन की ज़बरदस्त कमी आ गई है. इस बीच भारत ने अपने घरों के लिए एलपीजी की सुलभता को जारी रखा है और बाहरी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बड़े पैमाने पर स्थिरता को सुनिश्चित किया है. भारत अपनी एलपीजी की 60 फीसदी ज़रूरत के लिए आयात पर निर्भर है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ज़रिए वैश्विक आपूर्ति के केंद्रीकरण को देखते हुए, सरकार ने आपूर्ति सुरक्षित करने और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए तेज़ी से कदम उठाए. घरेलू उत्पादन बढ़ाने और कई भौगोलिक क्षेत्रों से सोर्सिंग में विविधता लाने जैसे उपायों ने सुनिश्चित किया कि आपूर्ति स्थिरता से होती रही. यही कारण है पूरे देश में एलपीजी का वितरण बड़े पैमाने पर जारी है; 1 मार्च 2026 से अब तक 18 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर डिलीवर किए जा चुके हैं और रोज़ाना 60 लाख से ज़्यादा सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है. डिलीवरी का औसत समय लगभग तीन दिन बना हुआ है. हालांकि कुछ स्थानों पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ा है. ये मामले ज़्यादातर स्थानीय और अस्थायी रहे हैं, जो मांग में अचानक बढ़ोतरी और लास्ट-माईल ऑपरेशनल परेशानियों की वजह से आए.

पारीख अध्यक्ष, डॉ. शर्मा सचिव बने

इंदौर. जायंट्स ग्रुप ऑफ़ मालवा इंदौर के चुनाव में समाजसेवी एम जी पारीख अध्यक्ष एवं डॉ. प्रवीण शर्मा मानद सचिव निर्वाचित हुए. चुनाव अधिकारी जायंट्स की सेंट्रल कमेटी के सदस्य एन सी एफ श्याम गोयल की देखरेख में हुए चुनाव में उपाध्यक्ष प्रथम पद के लिए अनिल खंडेलवाल तथा उपाध्यक्ष द्वितीय पद पर महेश गिरी और कोषाध्यक्ष पद के लिए सुरेश जैन सर्वानुमति से चुने गए. चुनाव अधिकारी ने बताया कि कार्यकारिणी में एन एल जैन, शकुन गोयल, कामिनी पांडे, उमा व्यास का मनोनयन किया गया. नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और संचालक मंडल सदस्यों को डॉ. वीपी सिंहल, डॉ. के एम शर्मा, विष्णु बिंदल, ओम बंसल आदि ने बधाइयाँ देते हुए शुभकामनाएँ व्यक्त की हैं.

कासलीवाल स्टार्टअप इन्क्यूबेशन फाउंडेशन का सक्षमी प्रोग्राम शुरू

इंदौर. सेंट्रल इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अरिहंत कॉलेज द्वारा समर्थित कासलीवाल स्टार्टअप इन्क्यूबेशन फाउंडेशन ने आई आई टी और आई आई एम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के 60 से अधिक मेंटर्स के साथ एम ओ यू पर साइन किए. सक्षमी एक संरचित इन्क्यूबेशन प्रोग्राम है, जो स्टार्टअप्स को आइडिया स्टेज से लेकर निवेश के लिए तैयार होने तक सहयोग प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है. इस प्रोग्राम का मुख्य फोकस एग्री, फूड और हेल्थ टेक जैसे अनंत संभावनाओं वाले क्षेत्रों पर है. शुभारंभ के अवसर पर एस.एन. मंडलोई, गौरव गोयल, विजय चौरें, नवीन खंडेलवाल, अशोक सुयाल, डॉ. राजबीर सिंह, डॉ. अनीता क्षेत्री, अंकिता नेमा, विवेक अस्थाना, अतुल जैन, सीए मंगेश काकरे, आयुष सोनी एवं ऋषभ पाटीदार जैसे विशेषज्ञों ने उद्यमिता और मेंटरशिप पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए. मेंटर्स एवं विषय विशेषज्ञों का सम्मान अरिहंत कॉलेज के चेयरमैन जयंन्त कासलीवाल, सेक्रेटरी कुणाल कासलीवाल, सीईओ डॉ. कविता कासलीवाल कोठारी एवं प्राचार्य डॉ. विवेक कापरे द्वारा मोमेंटो एवं सैपलिंग के साथ किया गया.

प्रशासन ने दो सौ करोड़ की जमीन कराई अतिक्रमण से मुक्त

▶ चोइथराम हॉस्पिटल के सामने सरकारी जमीन से हटाया कब्जा

नव भारत न्यूज

इंदौर. आज प्रशासन ऑफ नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो सौ करोड़ रुपए मूल्य के भेष्किमत सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई. उक्त जमीन पिपलिया राव क्षेत्र में चौइथराम हॉस्पिटल के सामने स्थित है, जिस पर वर्षो से एक सिख परिवार का कब्जा था.

आज प्रशासन और नगर निगम के रिमूवल दस्ते ने चोइथराम हॉस्पिटल के सामने बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. ग्राम पिपलिया राव के सर्वे क्रमांक 19/1, 20/1, 21/1 और 22/2 में चोइथराम अस्पताल के सामने स्थित है. इसका कुल रकबा 1.784 हेक्टेयर है. इस भूमि पर खुशबीर सिंह पिता दलजीत सिंह का लंबे समय से कब्जा था. राजस्व न्यायालय से प्रकरण में अतिक्रमण हटाने के आदेश हुए थे. 25 फरवरी 2026 को अंतिम सूचना पत्र जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे. कार्रवाई के दौरान एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर, तहसीलदार राकेश सस्तिया, कमलेश कुशवाह, नायब तहसीलदार डीपी सोनी, निगम रिमूवल अधिकारी अंकेश बिरथरे, बबलू कल्याणे और पुलिस विभाग के अधिकारी और निगमकर्मी उपस्थित थे.

जारी रहेगी कार्रवाई

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इंदौर जिले में कल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी होगी शुरू

नवभारत न्यूज

इंदौर. जिले में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कलेक्टर शिवम वर्मा ने मानपुर क्षेत्र के बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था बाबा महाकाल वेयर हाउस सहित अन्य खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं.

जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारु के अनुसार किसानों की सुविधा के लिए स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अब तक 1142 किसानों ने स्लॉट बुक कराया है. जिले में 10 अप्रैल से 5 मई तक 90 उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी होगी. किसान एमपी ऑनलाइन, सीएससी केंद्र या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने नजदीकी केंद्र और उपज बेचने की तिथि चुन सकते हैं.

पश्चिम क्षेत्र में कुसुम योजना से सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि

नवभारत न्यूज़

इंदौर. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों और जमीन मालिकों द्वारा 77 स्थानों पर कुल 234 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं. कुसुम ए में बंजर व कृषि भूमि पर 0.5-2 मेगावाट तक के प्लांट लगाए जा सकते हैं, जबकि कुसुम सी में विद्युतीकृत कृषि पंपों की खपत के बराबर या अधिक बिजली उत्पादन कर अतिशेष शासन को उपलब्ध कराया जाता है. योजना से किसानों की आय बढ़ती है, सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होती है और शासन द्वारा भुगतान व 30त्न सब्सिडी प्रदान की जाती है. अप्रैल में 45 नए आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, और अगले महीनों में सौ से अधिक नए प्लांट लगने की संभावना है.

एक नजर में ▶ गन्ने के रस और आइस उत्पादों में स्वास्थ्य से खिलवाड़

अस्वच्छ बर्फ के उपयोग से बढ़ रहा खतरा

नवभारत न्यूज

इंदौर. बाजार में गन्ने के रस में इस्तेमाल होने वाली बर्फ गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है, क्योंकि यह अक्सर औद्योगिक नॉन एडिबल बर्फ होती है. जो असुरक्षित खाद्य पदार्थों के उपयोग को उजागर करती हैं. अस्वच्छ बर्फ कई वेंडर सस्ती और औद्योगिक बर्फ का उपयोग करते हैं, जो पीने योग्य पानी से नहीं बनती और इसमें कीटाणु हो सकते हैं.

खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि खाद्य बर्फ के नमूनों की जांच, कार्रवाई पूरे महीने जारी रहेगी क्षेत्र में बर्फ (आइस) निर्माण के कुल 50 यूनिट संचालित हो रहे हैं, जिनमें 8 लाइसेंसधारी और 42 पंजीकृत इकाइयाँ शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इस सप्ताह जांच अभियान के तहत खाद्य बर्फ के 3 नमूने लिए गए. इनमें से 2 नमूने निर्माण इकाइयों से और 1 नमूना एक रेस्टोरेंट से लिया गया है. विभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान पूरे महीने लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जांच प्रक्रिया और मानक-खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी के अनुसार विभाग द्वारा समय-समय पर बर्फ के सैंपल लेकर लैब में परीक्षण कराया जाता है. यदि सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरते, तो संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है. हालांकि वर्तमान अभियान के दौरान किसी प्रकार की औपचारिक शिकायत सामने नहीं आई है, बल्कि यह कार्रवाई नियमित जांच का हिस्सा है.

लाइसेंस और नियम अनिवार्य-खाने योग्य (एडिबल) बर्फ बनाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है. बर्फ केवल आरओ प्लांट के शुद्ध पानी से ही बनाई जानी चाहिए. इसके साथ ही उत्पादन स्थल की साफ-सफाई, कर्मचारियों की मेडिकल जांच और स्वच्छ परिवहन सुनिश्चित करना जरूरी है. नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाती है.

खाद्य और औद्योगिक बर्फ में अंतर-मनीष स्वामी ने बताया कि खाने वाली बर्फ पीने योग्य स्वच्छ पानी से तैयार की जाती है, जबकि औद्योगिक बर्फ का उपयोग केवल बाहरी ठंडक के लिए होता है.

जमीनी हकीकत-नवभारत संवाददाता द्वारा गन्ने के रस के ठेलों पर वस्तुस्थिति जानने की कोशिश की गई. इस दौरान कुछ स्थानों पर बर्फ को अस्वच्छ थर्माकोल बॉक्स में रखा हुआ पाया गया, जहां बर्फ के साथ गंदगी भी नजर आई. हालांकि गन्ने का रस निकालने वाली मशीन (चरखी) में भी सफाई की कमी दिखी. साफ-सफाई को लेकर अभी भी जमीनी स्तर पर सुधार की आवश्यकता है.

स्वास्थ्य पर असर- डॉक्टर का बयान

डॉक्टर आर डी लोधी के अनुसार, यदि अस्वच्छ या अखाद्य बर्फ का उपयोग किया जाए तो इससे पेट संक्रमण, डायरिया, पीलिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खासकर बच्चों में इसका असर अधिक गंभीर हो सकता है.

लोगों के लिए सलाह-डॉक्टर लोधी ने लोगों को सलाह दी है कि गन्ने का रस, पानी बताशे और आइसकैंडी जैसी चीजों का सेवन करते समय साफ-सफाई और बर्फ की गुणवत्ता का ध्यान रखें, ताकि बीमारियों से बचा जा सके. कोशिश करें कि बिना बर्फ का गन्ने का रस पिएं. ऐसे वेंडर से बचें जो बर्फ को खुले में रखते हैं या अस्वच्छ दिखते हैं.